नं. जेड-14014/1/2021-जीसी एण्ड पार्लि. (ई-3010921)

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन,
नई दिल्ली-110011,
दिनांक: 24.11.2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अक्तूबर, 2021 माह के दौरान भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार- के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को अक्तूबर, 2021 माह के लिए भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों के मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

संलग्नकः यथोक्त।

अर्जुन राणा

(अर्जुन राणा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23044653

सेवा में,

मंत्री परिषद के सभी सदस्य।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली -110004
2. भारत के उप-राष्ट्रपति के सचिव, नं. 5, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली -110011
3. भारत के प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली -110011
4. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
6. सचिव, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
7. सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।

8. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।
9. सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली।
10. सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली।
11. सचिव, विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली।
12. सचिव, खान मंत्रालय, नई दिल्ली।
13. सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली।
14. सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
15. सचिव, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली।
16. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली।
17. सचिव, व्यय विभाग, नई दिल्ली।
18. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।
19. सचिव, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
20. सचिव, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली।
21. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
22. तकनीकी निदेशक, (एनआईसी), भूमि संसाधन विभाग, को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. माननीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री के निजी सचिव।
2. माननीया राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण) के निजी सचिव।
3. माननीय राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास तथा इस्पात) के निजी सचिव।

<u>अक्तूबर, 2021 माह के दौरान भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार</u>

1. रक्षा मंत्रालय को दिनांक 05.10.2021 को अरुणाचल प्रदेश में कतिपय भूमि के अर्जन के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) के अधीन "समुचित सरकार" अधिसूचित किया गया था।

2. सचिव (एलआर) ने दिनांक 04.10.2021 को "मातृभूमि"- विभाग की एक एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली, जिसे विकसित किया जा रहा है, को तैयार करने के बारे में बैठक की अध्यक्षता की।

3. विभाग ने बहुभाषी भूमि अभिलेखों के लिए सॉफ्टवेयर को तैयार करने की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सी-डैक टीम, पुणे के साथ दिनांक 20.10.2021 को विडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से बैठक आयोजित की।

4. सचिव (एलआर) ने दिनांक 26.10.2021 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएफएमएस कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता की।

5. सचिव (एलआर) द्वारा दिनांक 07,12,14 और 25 अक्तूबर, 2021 को आयोजित बैठकों की श्रृंखला के माध्यम से "लंबित मामलों के निपटान और स्वच्छता पर चलाए जा रहे विशेष अभियान" की प्रगति की समीक्षा की गई और 18, 20 और 22 अक्तूबर, 2021 को सभी परिसरों का निरीक्षण किया गया।

6. दिनांक 02 से 31 अक्तूबर, 2021 के दौरान चलाए गए "लंबित मामलों के निपटान और स्वच्छता के विशेष अभियान" के भाग के रूप में विभाग ने 11028 फाइलों की समीक्षा की तथा 5734 अप्रयुक्त और पुरानी फाइलों का नष्टीकरण किया गया। फाइलों के नष्टीकरण, इलैक्ट्रॉनिक कबाड़ तथा नाकारा वाहनों को हटाने के परिणामस्वरूप, 2206 वर्ग फुट स्थान खाली किया गया है।

7. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के अधीन अब तक कुल 6382 {(8214 (संस्वीकृत)- 1832 (राज्यों को हस्तांतरित)} परियोजनाओं

में से 5151 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अभी तक 3807 परियोजनाओं का एंडलाइन मूल्यांकन पूरा हो चुका है।

8. डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के विभिन्न घटकों की प्रगति (संचयी) की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैः

i. 6,00,879 गांवों का भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण पूरा किया गया।
ii. 4,883 उप रजिस्ट्रार कार्यालयों में रजिस्ट्रीकरण का कंप्यूटरीकरण पूरा किया गया।
iii. 11,094,349 भूकर मानचित्रों/एफएमबी/टिप्पनों का डिजिटलीकरण पूरा किया गया।
iv. 3,971 उप रजिस्ट्रार कार्यालयों का भूमि अभिलेखों के साथ एकीकरण पूरा किया गया।
v. 2,508 तहसीलों में आधुनिक अभिलेख कक्षों की स्थापना पूरी की गई।

*****